by completing all the construction in time. I hope, it would continue the spirit of dedication by rectifying the defects and by bringing the erring performance to book.

SHRI BUTA SINGH: I am happy the hon. Member has appreciated the wonderful work done by the DDA during the Asiad. I want to assure the honourable House that it will be my endeavour and that of the team led by the Vice-Chaiman of the DDA....

MR. DEPUTY SPEAKER: Fortunately. you were the Minister in-charge also.

SHRI BUTA SINGH:....to keep up the spirit and also maintain the quality and speed with which we were able to get through the Asiad.

It is not our intention to justify any unfortunate incident that tasks places. But if you look at the huge programme which is undertaken by the DDA and look at the four incidents which took place during the last one year or so, it will not be to the extent that one can get panicky. As the hon. lady member has said, there is nothing to get panicky about it. If you just look at the figures of our programme, in 1981-82; it was 20,000 houses; in 1982-83, it was 25,000 houses and at the moment 55,000 houses are under construction. To take up a few instances here and there and to say that some panic has been created will not be justified. I would request the hon. lady member not to get panicky. The DDA is very much in the grip of the situation and we are not letting anything to escape our notice.

MR. DEPUTY SPEAKER: She got panicky because the person who died was a lady.

SHRI BUTA SINGH: Whether it is a lady or a child or an old man, any life lost during the construction project is a valuable life lost. To that extent, I share her anxiety. We will see to it that such incidents are not allowed to be repeated.

She asked about the quality of mixture being used in the DDA schemes. May I inform the hon. lady member that there is a regular material quality control check being undertaken in and outside the test houses by the ITT experts and we are keeping a constant consultation with this expert body. There is also in the DDA itself a quality control cell which monitors the quality of various projects under its purview.

The incidents which the hon. lady member mentioned are not in the north and the west. One is in the south and the other is in the north. We do not have any discrimination; we look after all corners of Delhi and we treat Delhi as one compact capital project. Wherever defects are noticed, whether it is east or west or north or south, we immediately rush to the spot and try to rectify the defects.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: What about mixing Badarpur coal dust with cement?

SHRI BUTA SINGH: As I already mentioned, we have set up an expert committee both to monitor the quality as well as the cost, etc. This point which my hon. friend has made will be taken care of. I will ask the expert committee to go into it.

She mentioned something about the cement check system. It has recently been re-vamped and we are constantly inspecting the under-weight cement bags. We are also making random checks. I can assure the House that we will not allow anybody to play with the materials which are stored in our godowns.

13.10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Seventeen minutes past Fourteen of the

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to establish on Agricultural University at Ochhaghat in Solan.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Navin Ravani. He is not here. Shri Krishan Datt Sultanpuri.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के ओछघाट स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कदम उठाये गये थे । परन्तु इस स्थान से कृषि विश्वविद्यालय का स्थानान्तरण करके पालनपुर, जिला कांगड़ा में ले जाया गया । हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार भारत सरकार से यह मांग करती चली आ रही है कि सोलन जिला की ओछघाट स्थान पर जो सत्यानन्द स्टोक्स के नाम से कृषि विद्यालय का काम्लेक्स बना हुआ है वह वागवानी फोरस्ट्री यूनिवर्सिटी में बदला जाय क्योंकि इस समय पहाड़ी क्षेत्रों को वनों और फलों की अधिक आवश्यकता है कि उस पर अनुसंधान किया जाय और इस संबंध में लोक सभा के बहुत से सदस्यों ने मांग की थी कि उसको उद्यान विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय । परन्तु अभी तक इस संबंध में भारत सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये । मैं भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में उपरोक्त यूनिवर्सिटी खोली जाय और उसको भारत सरकार अधिक से अधिक मदद दे ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में वन और फल उत्पादन के बारे में अधिक से अधिक अनुसंधान किया जा सके ।

(ii) Establishment of Industries in Mirzapur.

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला एक लम्बे क्षेत्रफल का जिला है । इसकी लम्बाई लगभग 300 किलोमीटर है । जिले के दक्षिणी भाग में बिजली का कारखाना होने के कारण कई बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो गये हैं तथा कोयले का भण्डार मिलने के कारण अनेक बड़े-बड़े तापिय बिजली गृह स्थापित हो र हैं और इसी कारण अन्तय उद्योगों की भी उसी क्षेत्र में स्थापित होने की सम्भावनायें हैं । किन्तु जिले का उत्तरी भाग उद्योग विहीन है । हमारे क्षेत्र का पुराना मिर्जापुर शहर उजड़ता जा रहा है । किसी समय लाख, रुई, बर्तन आदि उद्योगों के कारण विन्ध्याचल का यह शहर एक जीवन्त और प्रसिद्ध शहर रहा है । आज उक्त उद्योग भी समाप्त प्राय: हैं । लोग यहां से भाग रहे हैं और दक्षिणांचल में जा रहे हैं । शहर के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी विकास से वंचित हो रहा है । बेरोज़गारी से लोग पीड़ित हैं और भाग कर बम्बई, कलकत्ता और अन्य शहरों की ओर जा रहे हैं, अत्यन्त निराशा तथा हताशा व्याप्त है । अत: केन्द्रीय सरकार तथा उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि मिर्जापुर विन्ध्याचल के पास सार्वजनिक क्षेत्र, निजी या सहकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाय ।

(iii) Demand for re-opening of Bihar Cotton Mills Limited, Phulwari Sharieff, Bihar.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय बिहार की राजधानी पटना के निकट फुलवारी शरीफ में बिहार काटन मिल्स लि॰ वर्षों से काम करता आ रहा था । पहले वहां मोटा कपड़ा और सूत दोनों का उत्पादन होता था, बाद में केवल सूत का उत्पादन होने लगा । इसके लिए मिल मालिकों को कपास का कोटा मिलता था, जो संभवत: आज तक जारी है । कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग नौ सौ है, जिनमें अधिकांश स्थानीय और कुछ बाहर के मजदूर हैं । उन मजदूरों पर उनके परिवार के हजारों व्यक्तियों की रोटी निर्भर है ।

परन्तु दु:ख है कि कारखाने के मालिकों ने सरकार से अनुमति लिए बगैर अकस्मात 20 जुलाई, 1982 को